सहकारिता विभाग उ०प्र० समीक्षा बैठक

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में

दिनांक: 12 सितम्बर 2025

मा० केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में

> "सहकार से समृद्धि" - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र का व्यापक विकास

राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना

उद्देश्य

सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को प्रोत्साहित करना

केंद्रीय सहयोग

मा० केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया

भविष्य की दिशा

उत्तर प्रदेश सहकारिता क्षेत्र में नए इतिहास रचने की दिशा में अग्रसर

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा

यूपी में राज्य सहकारी डिग्री कॉलेज खुलेगा : मुख्यमंत्री

तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की तैयारी के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में एम-पैक्स सदस्यता महाभियान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' मंत्र को आत्मसात करते हुए 12 सितम्बर से 12 अक्तूबर तक आयोजित अभियान के माध्यम से हर किसान और हर ग्रामीण परिवार को सहकारिता से जोड़ना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम सदस्यता महाअभियान में 30 लाख से अधिक नए सदस्य जुड़े थे, जिनमें 17.33 लाख किसान, 3.92 लाख अकुशल श्रमिक, 1.56 लाख कुशल श्रमिक, 2.20 लाख पशुपालक और 6,411 मत्स्यपालक शामिल थे। इस अभियान से सहकारिता क्षेत्र में ₹70 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि द्वितीय महाअभियान को और व्यापक बनाया जाए तथा गांव-गांव में कैंप, ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं और प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैठक में सहकारी बैंकिंग सुधारों की समीक्षा करते हुए अवगत कराया गया कि 2017-18 से 2024-25 तक राज्य सरकार द्वारा 16 बंद जिला सहकारी बैंकों को ₹306.92 करोड़ की सहायता से पुनर्जीवित किया गया है। इन बैंकों का एनपीए 2017 में ₹800 करोड़ से घटकर मार्च 2025 में ₹278 करोड़ रह गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 15 नवम्बर 2025 तक वित्तीय समापन प्रक्रिया पूरी कर जनवरी 2026 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण किसानों की समृद्धि का आधार है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को केन्द्रीय राज्य मंत्री सहकारिता, मुरलीधर मोहोल एवं राज्यमंत्री जेपीएस राठौर ने शिष्टाचार भेंट की।

अस्पतालों के पास खुलें जनऔषधि केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्र अस्पतालों के निकट स्थापित किए जाएं और सहकारिता को युवाओं के लिए कृषि, डेयरी, मत्स्य व सेवा क्षेत्रों में रोजगारमूलक अवसरों का द्वार बनाया जाए। बैठक में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रकाश शाही, धर्मपाल सिंह, संजय निषाद, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, भारत सरकार के सचिव सहकारिता डॉ. आशीष कुमार भूटानी, नाबार्ड के डीजीएम एनएल साहू तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

12 अक्तूबर तक सदस्यता अभियान

16 बंद जिला सहकारी बैंकों पुनर्जीवित किया

पांच साल में दो लाख नये पैक्स स्थापित होंगे

लखनऊ। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। आगामी पांच सालों में देश में दो लाख नए पैक्स बनाने का लक्ष्य है। तब देश में कोई पंचायत ऐसी नहीं बचेगी, जहां सहकारिता की पहुंच न हो। ये बातें शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहीं। वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सहकारिता विभाग के एम-पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 का शुभारंभ कर रहे थे।

विभाग में जल्द नई भर्तियां होंगी:राठौर

सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो सहकारिता को मजबूती देने की मुहिम शुरू हुई है, यूपी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने इस मौके पर घोषणा की कि सहकारिता विभाग में जल्द नई भर्तियां की जाएंगी। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी केवल खेती नहीं बल्कि पशुपालन से भी होगी। मत्स्य विभाग के मंत्री डा. संजय निषाद ने कहा कि पहले सहकारी समितियां दोहन का साधन थीं। मोदी सरकार में अब ये किसानों के विकास का संसाधन हैं।

एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान

2025
International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश

1 प्रथम महाअभियान (2023)

30 लाख+ नए सदस्य जुड़े

- 17.33 लाख किसान
- 3.92 लाख अकुशल श्रमिक
- 2.20 लाख पशुपालक

अंशदान: **₹70 करोड़**

2 द्वितीय महाअभियान (2025)

12 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक

हर किसान और हर ग्रामीण परिवार को सहकारिता से जोड़ना

गाँव-गाँव में कैंप और जागरूकता कार्यक्रम

प्रदेश में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय : योगी

लखनऊ (एसएनबी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की तैयारी के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

- मुख्यमंत्री ने की प्रदेश के सहकारिता विभाग की समीक्षा
- 12 अक्टूबर तक एम-पैक्स सदस्यता महाभियान, हर किसान-परिवार को सहकारिता से जोड़ने का संकल्प

बैठक में एम-पैक्स सदस्यता महाभियान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' मंत्र को आत्मसात करते हुए 12 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक आयोजित अभियान के माध्यम से हर किसान और हर ग्रामीण परिवार को सहकारिता से जोड़ना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम सदस्यता महाअभियान में 30 लाख से अधिक नए सदस्य जुड़े थे, जिनमें 17.33 लाख किसान, 3.92 लाख अकुशल श्रमिक, 1.56 लाख कुशल श्रमिक, 2.20 लाख पशुपालक और 6,411 मत्स्यपालक शामिल थे। इस अभियान से सहकारिता क्षेत्र में रु. 70 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ था।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि द्वितीय महाअभियान को और व्यापक बनाया जाए तथा गाँव-गाँव में कैंप,

ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है और प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बैठक में सहकारी बैंकिंग सुधारों की समीक्षा करते हुए अवगत कराया गया कि 2017-18 से 2024-25 तक राज्य सरकार द्वारा 16 बंद जिला सहकारी बैंकों को रु 306.92 करोड़ की सहायता से पुनर्जीवित किया गया है। इन बैंकों का एनपीए 2017 में रु 800 करोड़ से घटकर मार्च 2025 में रु 278 करोड़ रह गया। मार्च 2025 तक रु 1000 करोड़ का ऋण व्यवसाय दर्ज हुआ और सभी बैंक लाभ में आ गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और जमाकर्ताओं का विश्वास ही सहकारिता की असली पूँजी है, इसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाए।

उन्होंने कहा कि सहकारिता भारतीय ग्रामीण समाज की प्राचीन परंपरा है। समाज को एकजुट रखने में इसकी बड़ी भूमिका है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सहकारिता क्षेत्र में नए इतिहास रच रहा है।

अन्न भंडारण योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि एफसीआई ने प्रदेश के 35 जनपदों में 96 स्थलों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 15 नवम्बर 2025 तक वित्तीय समापन प्रक्रिया पूरी कर जनवरी 2026 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण किसानों की समृद्धि का आधार है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इस अवसर पर एम-पैक्स के गठन और कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। बताया गया कि 2024-25 में 266 एम-पैक्स के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 457 नये एम-पैक्स गठित हो चुके है, जबकि सितम्बर माह में 1,088 ग्राम पंचायतों में संगठन प्रक्रिया चल रही है। एम-पैक्स को उर्वरक वितरण हेतु ₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण सीमा दी गई है, जिससे अब तक ₹5,400 करोड़ का टर्नओवर और ₹120 करोड़ की मार्जिन मनी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, 757 नवगठित एम-पैक्स के उन्नयन के लिए राज्य सरकार ₹1 लाख मार्जिन मनी तथा रु 1 लाख आधारभूत अवसंरचना विकास के लिए उपलब्ध करा रही है।

डिजिटल भुगतान व्यवस्था के तहत 6,101 सोसाइटी में क्यूआर/यूपीआई आधारित प्रणाली लागू हो चुकी है। साथ ही, व्यवसाय विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए 5170 एम-पैक्स में सीएससी सेवाएं, 6443 एम-पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्र तथा 161 एम-पैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्र अस्पतालों के निकट स्थापित किए जाएं और सहकारिता को युवाओं के लिए कृषि, डेयरी, मत्स्य व सेवा क्षेत्रों में रोजगारमूलक अवसरों का द्वार बनाया जाए।

सहकारी बैंकिंग सुधार की सफलता

16

बंद बैंकों का पुनर्जीवन

₹306.92 करोड़ की सहायता से जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित किया गया

₹522 cr.

एनपीए में कमी

2017 में ₹800 करोड़ से घटकर मार्च 2025 में ₹278 करोड़

₹1000 cr.

ऋण व्यवसाय

मार्च 2025 तक ₹1000 करोड़ का ऋण व्यवसाय दर्ज, सभी 16 DCBs लाभ में

16 बंद DCBs में 2100 करोड़ से 18 लाख से अधिक जमाकर्ताओ का हुआ भुगतान

"किसान और जमाकर्ताओं का विश्वास ही सहकारिता की असली पूँजी है"
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

एम-पैक्स विकास और भविष्य की योजनाएं

वर्तमान उपलब्धियां

10 लाख ब्याज मुक्त ऋण सीमा

उर्वरक व्यवसाय हेतु

₹5,400 करोड़

टर्नओवर और ₹120 करोड़ मार्जिन मनी

6,101 सोसाइटी

डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू

457 नए एम-पैक्स

चालू वित्तीय वर्ष में गठित

अन्न भंडारण योजना

24 एम-पैक्स चिह्नित

लक्ष्य: अप्रैल 2026 तक पूर्ण निर्माण

व्यवसाय विविधीकरण

- 5,170 एम-पैक्स में सीएससी सेवाएं
- 6,443 पीएम किसान समृद्धि केंद्र
- 161 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

उत्तर प्रदेश सरकार

2025
International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

सहकारिता विभाग
उत्तर प्रदेश
संघे शक्ति सर्वदा

धन्यवाद